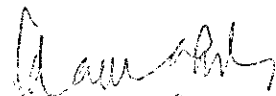


15

उत्तराखण्ड शासन  
परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग-2  
संख्या 15 / IX / 2011 / 66 / 2010  
देहरादून दिनांक 04 जून, 2011

### अधिसूचना

जो कि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।  
राज्य, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश अधिआवश्यक सेवाओं का अनुदान अधिनियम, 1986 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20 वर्ष 1986) की धारा 3 की उपधारा (1) कायदेत ओटोमोबिल विनियम अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड राज्य में लागू करने) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह की अवधि के लिए उत्तराखण्ड परिवहन नियम में कार्यरत कर्मियों की समस्त सेवाओं को अत्यावश्यक मानने घोषित करते हुए उनकी हड़ताल आदि को निषिद्ध करते हैं।

  
एसओ राधास्वामी  
प्रमुख सचिव।

संख्या 15 / IX / 2011 / 66 / 2010 तद्विनांक।

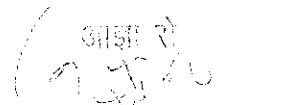
निर्देशिका- उप निदेशक, युवक एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय रुड़की जगपद हरिद्वार को हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति इस अनुरोध के साथ भेजित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आधारभूत मजदूर के विचारों परिशिष्ट में परिनिम्न आदेश के अन्तर्गत प्रकाशित कराने तथा उसकी 100 मुद्रित प्रतियाँ उप राज्य, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भेजने का कष्ट करें।

(गरिमा शैकली)  
उप सचिव।

संख्या 15 / IX / 2011 / 66 / 2010 तद्विनांक।

निर्देशिका- निम्नलिखित को सूचक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, सूचना उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ भेजित कि उक्त अधिसूचना को राज्य में प्रसारित होने वाले प्रमुख राजकार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 3- साधुवा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी एवं कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 4- राज्य निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन नियम, देहरादून।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- राधेश राधेश कर्मचारी यूनियन द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन नियम देहरादून।
- 7- राज्यपाल को भेजित कि परिसर में प्रकाशित करें।
- 8- कार्यवाही करें।

(आज्ञा से)  
  
(गरिमा शैकली)  
उप सचिव।